MR. CHAIRMAN: Yes, Now, we proceed to the half-an-hour discussion.

SHRI VASANT SATHE: Sir, why not we extend this half-an-hour discussion a little further? After his speech, which may take hardly five to 10 minutes, we can take up the half-an-hour discussion.

SOME HON. MEMBERS: No.

MR. CHAIRMAN: Shri Ramavatar Shastri to raise the discussion under rule 55(2).

17.29 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

UNREST AMONG THE JUNIOR DOCTORS

श्री रामअवतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, यह आध घण्टे की चर्चा मैं जूनियर डाक्टरों की हड़ताल के सम्बन्ध में उठा रहा हूं । आप जानते हैं कि दिल्ली के केन्द्र-चालित 9 अस्पतालों के जूनियर डाक्टर 1 जनवरी, 1974 से हड़ताल पर हैं और उन की तादाद 2500 है । उन की मांगों के समर्थन में हिन्दुस्तान के प्राय: सभी राज्यों में जूनियर डाक्टरों की हड़ताल फैल चुकी है ।

इस की वजह से सबसे रोगियों को होने वाली कठिनाइ का एहसास सभी को होगा । लेकिन दुख है कि सरकार अपनी झूठी प्रतिष्ठा की आड़ में इस समस्या का समाधान निकालने से कतरा रही है । डाक्टरों का पेशा कितना नोबल और कितना अच्छा है । इनको सभी जानते हैं । वे सीधे रूप में जनता की सेवा करते हैं और निकट जा कर उनको मदद करते हैं । इस पेशे के महत्व को समझते हुए ही हमारे देश के तेज से तेज छात्र इस पेशे में जाते हैं । साधारण बुद्धि के नहीं जाते । वे इसीलिए जाते हैं कि आई ए एस की नौकरी में जाने के बजाय इस पेशे में उनको जनता की सेवा करने का ज्यादा मौका मिलता है । यह उनकी पवित्र भावना इसके पीछे होती है । लेकिन आज आप कितने बुरे तरीके से उन के साथ व्यवहार कर रहे है । जब भी इस सवाल को सरकार के सामने उठाया जाता है तो या तो उनकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता और अगर दिया भी जाता है तो भीख की तरह 25—50 रुपये फेंक दिए जाते है, जैसे सब से बुरा काम वही करते हैं । हमदर्दी का सबूत आप उनके प्रति नहीं देते हैं । इसी वजह से उनको बार-बार आन्दोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है । यह पहली बार नहीं है । 1964 में उन्होंने आन्दोलन करने की कोशिश की । उस समय करमरकर कमेटी बिठाई गई । उसने भी कहा कि उनकी कठिनाइयां जायज है और हमदर्दी जाहिर की लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ । 1967 में उन्हें हड़ताल करनी पड़ी । 1969 में करनी पड़ी । 1969 के बाद कमेटी बिठाई गई और कहा गया कि रिपोर्ट आने के बाद फैसला होगा । वह भी नहीं हुआ । फिर 31 मार्च 1973 को आन्दोलन के फलस्वरूप सरकार से उनकी बातें हुई और आपके विभाग के सचिव ने उन से समझौता किया । उसके अनुसार उनकी कई बातों को स्वीकार किया गया । उन में से कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । पहली बात यह कही गई थी ।

> "The House-Surgeons and Post-Graduates are registered with the Medical Council of India and should, therefore be regarded as full-fledged doctors."

लेकिन सरकार अब इससे मुकर रही है । दूसरे यह कहा गया था :

> "In addition to academic pursuits, they also render useful service in patient care in the hospitals. Their designation and status should

be in consonance with the role they are actually playing."

इस बात से भी सरकार पीछे जा रही है । फिर यह कहा गया था :

"It was agreed that the strength of House-surgeons and Post-Graduates would depend upon the need of the individual teaching hospitals and also the availability of seats in the Post-Graduate course. Within these limits and in recognition of the two principles enunciated in para (3) above, it was agreed that the present system of House-Surgeons/Post Graduates along with stipends/scholarships thereof should be replaced by a system of Resident service with suitable running graded pay scales and allowances coupled with due process of selection at appropriate stages."

ग्रेटिड पे स्केल की बात मानी गई लेकिन आज सरकार उसके सिद्धान्त से भी पीछे जा रही है । यह सब से बड़ा सवाल है । अगर इसका रास्ता आप नहीं निकालते हैं तो समस्या का समाधान नहीं होगा । यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उनको स्केल दिया जाए कि नहीं । उसी एग्रीमेंट में कहा गया था :

It was agreed that stipends/scholarships shall be paid to all the Interns, all House-Surgeons and such of the Post-Graduates as are already in receipt of Government of India Scholarships at the following rates with effect from 1st March, 1973.

Interns	Rs. 225
House-Surgeons	Rs. 325
Post-Graduates	Rs. 350

इससे भी सरकार मुकर रही है । फिर समझौते की क्या वैल्यूडिटी है ? स्वास्थ्य सचिव श्री रामचन्द्रन साहब को पता नहीं अब आपके सचिव हैं या नहीं उन्होंने इस के बारे में कहा था:—(व्यवधान) यह भी समझौते में कहा गया था कि हम कमेटी बिठा रहे हैं और करतार सिंह कमेटी बिठाई गई । उस कमेटी को 30—9—73 तक अपनी रिपोर्ट दे देनी थी, पर उसने 31—12—73 तक भी रिपोर्ट नहीं दी । 10 जनवरी को दी । बड़े बेसब्र हो कर सरकार की ढीली ढाली नीति को देख कर डाक्टरों को 1 जनवरी से हड़ताल करनी पड़ी और अब उनकी नान प्रेक्टिसिंग एलाउंस की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है । दूसरों को आप दे सकते हैं, उनको क्यों नहीं ? जो डाक्टर एम०बी बी एस. मिलिटरी या दूसरी जगहों में हैं उनका पे स्केल ज्यादा है और आप इनको कम क्यों दे रहे हैं ? इसकी वजह से उनके अन्दर असन्तोष होना स्वाभाविक है । हमदर्दी के साथ उनसे व्यवहार करना तो दूर की बात है, सरकार उन से बात तक करने को तैयार नहीं । बात अगर करती है तो अपनी शर्तों पर करती है । उनको धमकियां दी गईं , क्वार्टरों से निकालने की कोशिश की गई और कितने ही डाक्टरों की सेवायें खत्म कर दी गई ताकि वह आप के सामने घुटने टेक दें । लेकिन अभी तक आप की यह चाल उन्हें दमन के जरिए कुचलने की कामयाब नहीं हो सकी और न हो सकेगी । यह चीज धीरे धीरे फैल रही है और आप ने भी कल के अखबारों में पढ़ा होगा कि इस के समर्थन में वकील आ रहे हैं, प्रोफेसर आ रहे है, दूसरे डाक्टर आ रहे है, शिक्षक आ रहे हैं, तरह तरह के संगठनों के लोग आ रहे हैं और उन लोगों ने फैसला किया है कि उन की मांगों के समर्थन में, जिन मांगों का जिक्र आप के साथ जो समझौता हुआ था उस मसौदे में किया गया था उन मांगों के समर्थन में वे लोग 13 मार्च को पार्लियामेंट में मार्च करेंगे और आप स मांग करेंगे कि आप उन के साथ वार्ता करिए, वार्ता के जरिए रास्ता निकालिये । वह भी कोई औद्योगिक मजदूरों की तरह स हड़ताल करने के आदी नहीं हैं ।

[श्री रामावतार शास्त्री]

वह सेवा करते हैं। आज भी वे क्लासेज लेते है, आउट डोर पेशेंट्स को देखते हैं। आप की इन दमनात्मक नीतियों के बावजूद वह पेशेंट्स को देख रहे हैं। तो यह जो आन्दोलन व्यापक बनता जा रहा है इस व्यापकता को सीमित और खत्म करने के लिए उन के साथ समझौता वार्ता आप क्यों नहीं करते है यह मैं जानना चाहता हूं।

सभापति महोदय : अभी और भी कुछ सदस्यों को प्रश्न पूछने है और मंत्री महोदय को उत्तर देना है। आप कृपया जल्दी समाप्त करें ताकि प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल सकें।

श्री रामावतार शास्त्री : सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन्होंने समझौते का दरवाजा बन्द कर दिया है या मंत्री जी के दर्वाजे का फाटक खुला हुआ है। यदि दरवाजा खुला हुआ है तो उन से पुनः बात कर के रास्ता क्यों नहीं निकालते ?

क्या यह बात भी सच है कि सीनियर डाक्टर्स भी चाहते हैं कि आप उन के साथ समझौता करें ? वे बीच-बचाव करना चाहते हैं लेकिन सरकार कोई खिडकी इस के लिए नहीं खोलना चाहती, जिस की वजह से कठिना हो रही है।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि ——अब उन्होंने जो मांग रखी है—वैसे तो आप ने बार-बार कहा है कि आप सिद्धान्त से सहमत हैं——तो फिर उन के औचित्य में आप को क्यों सन्देह है। जब दूसरों को आप वे चीजें दे रहे हैं तो इन के साथ विमाता जैसा व्यवहार क्यों करना चाहते हैं ?

हम इन बातों का समाधान चाहते हैं ताकि यह मसला हल हो, वरना स्थिति बहुत गम्भीर हो जायगी और सरकार को लेने—के—देने पड़ जायेंगे, फिर बहुत सारे लोग उनके साथ चले जायेंगे। हम चाहते हैं कि आप ऐसा जवाब दें ताकि कल समझौता-टेबिल पर बैठ कर उन के साथ बातचीत कर के रास्ता निकाल सकें।

श्री जगन्नाथ मिश्र (मधुबनी) : सभापति महोदय, मुझे बडी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री डा० करण सिंह अपनी निष्पक्षता, कर्मठता और उदारता के लिए देश में और इस सदन में कितने प्रशस्त है। वे यह भी अच्छी तरह से जानते है कि मानव जीवन मे डाक्टरों का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थिति मे जूनियर डाक्टरों की हड़ताल पर जाना इनके लिए कितना दुखद रहा होगा ——यह अनुमान करने की बात है और इन्होंने अपने कर्तव्य और स्वभाव के अनुरूप ही एक बार नहीं अनेकों बार समझौते का हाथ बढाया है ——इस लिए वे हमारे धन्यवाद के पात्र है। लेकिन यह बडा दुखद है कि समझौता नहीं हो सका और डाक्टर अभी भी हड़ताल पर है।

इसी पृष्ठभूमि मे मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि क्या यह सत्य है कि डिमास्ट्रेटर और हाउस-मैन की योग्यता एक है तथा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने के लिए दोनो को समान सुविधायें प्राप्त है ? डिमास्ट्रेटर सिर्फ वर्किंग-आवर मे काम करते है, जब कि हाउसमैन 14 घण्टे तक काम करते है, वैसे तो उन्हें 24 घण्टे काम पर रहाना पडता है। डिमास्ट्रेटर को टीचिंग एक्सपीरियेन्स मिलता है और हाउस मैन को नही। डिमास्ट्रेटर लिए बैठने की सुविधा है लेकिन हाउसमैन के लिए वह भी नही है।

स्वास्थ्य मंत्री महोदय हाउसमैन के लिए 500 रुपया और डिमास्ट्रेटर को 900 रुपया मासिक वेतन किस आधार पर न्यायोचित मानते हैं। यदि वे कहते है कि डिमास्ट्रेटर का एप्वाइन्टमेन्ट यूनियन पब्लिक सर्विस

कमीशन से होता है और हाउसमैन का एप्वाइन्टमेंन्ट हास्पिटल सुप्रीन्टेडेन्ट के द्वारा होता है तो क्या वे इन के एप्वाइन्टमेन्ट को भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कराने की व्यवस्था करेंगे ?

महोदय, मैं मंत्री महोदय से इन प्रश्नों को स्पेसिफिक और ठोस जवाब जानना चाहता हूं ।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Sir, at the very outset, I must congratulate young doctors, my sisters and brothers, for their wonderful united action and unity which they have maintained ever after all the repressive measures adopted by the Government, including termination of services.

I would like to know from the hon. Minister, Dr. Karan Singh, who is not capable of being harsh to anyone why that particular agreement which was signed with the doctors at the Secretary's level was not implemented. In their brochure, they have clearly mentioned that this is the crux of the matter. The junior doctors have demanded no more than the implementation of the agreement. They ask: Is this a crime?

Then, about non-practising allowance, I am told that the Political Affairs Committee which met recently—it had come out in the papers; I am speaking subject to correction—have already taken a decision that Rs. 150 or 160—I do not know—should be given as non-practising allowance. I would like to know from the hon. Minister whether fresh negotiations will start and whether they will be entitled to this non-practising allowance and whether the salient or main features of the agreement which was entered into by the Health Secretary on the 31st March 1973 will be implemented in letter and spirit.

My only fear is that, unless persons of the calibre of Dr. Karan Singh rise above he network of bureaucrats, we will not be able to help the doctors or technocrats. In this case some of the bureaucrats may advise him correctly, but some may mislead also. Let him take us into confidence. A small Committee of this House can be appointed. I am prepared to offer my services. We are not experts only in settling the nurses problem. We can settle the problem of doctors also. Let him rely on our wisdom once at least and not rely on the wisdom of bureaucrats; and I am sure the matter will be settled.

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरैना) : सभापति जी, मैं मंत्री महोदय से दो-तीन बातें जानना चाहूंगा डाक्टर करण सिंह जी ने साहित्य में डाक्टरेट की डिग्री पाई है, इसलिये इस ओर उन का विशेष ध्यान नहीं है । अगर वे एम०बी०बी०एस० होते तो समस्या कभी की हल हो जाती ।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : राजनीति में नहीं है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अगर आप एम०बी०बी०एस० होते तो जल्दी समस्या हल हो जाती ; डाक्टर बनने मे 80 हजार रुपया उस की पढ़ाई पर खर्च होता है । इतना पैसा खर्च होने के बाद वह डाक्टर बनता है और उस का वेतन, जो आप देते हैं, आज की मंहगाई के साथ तुलना करेंगे तो मुझे विश्वास है आप स्वयं भी दिल से कहेंगे कि जो कुछ उन को मिलता है, वह कम मिलता है, उन्हें ज्यादा मिलना चाहिये । इस के लिये आप भी अन्दरूनी प्रयास कर रहे हैं कि कैसे दें, लेकिन जब ऊपर से नहीं मिलता है तो आप हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत दयालु और उदार हृदय के हैं ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (भाजापुर) : दोनों कारण हैं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : जुनियर डाक्टरो की मांगों को लेकर 31 मार्च, 1973 को एक समझौता हुआ, उस समझौते को सरकार द्वारा अमल मे क्यो नही लाया गया ? उस का मूल कारण क्या है ? जब समझौता हुआ तो किन किन मुद्दो पर हुआ था ? जब सरकार एक चीज को मान गई तो उस के बाद दिया क्यो नही, क्यो कार्यान्वित नही किया गया, कौन सी कठिनाई आप के सामने थी—यह बात सामने आनी चाहिये ?

जुनियर डाक्टर्स सप्ताह मे 100 घन्टे से अधिक काम करते है, लगातार पूरा समय दे कर काम करते है, लेकिन जो दूसरे डाक्टर है वे सप्ताह मे 28 घन्टे काम करते है, इन डाक्टरो को 900 रुपये देते है जब कि 100 घन्टे काम करने वाले डाक्टरो को 225 से 350 रुपये तक देते है—इतना भेदभाव क्यो है ? आप के यहा एक कमेटी बनी थी जिस मे बहुत सी बाते कही गई, आप ने इस सिद्धान्त को भी माना है कि समान काम का समान वेतन होना चाहिये । जब वे एक जैसा काम करते हैं तो उन को समान वेतन मिलना चाहिये .

श्री बसंत साठे (अकोला) कछवाय जी, आप बहुत पुरानी बात कह रहे हैं, अब तो यह 550 रुपये हो गया है, 250—300 रुपये नही है ।

श्री फूल चन्द वर्मा (उज्जन) : वह बेसिक है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं जानना चाहता हू यह जो लोग हैं काफी बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग है, इनकी सेवा से काफी लोगों का उद्धार होता है लेकिन आज दिल्ली के अस्पतालों मे इतनी खराब हालत है कि जबसे हडताल चली है कितने ही लोग मौत के घाट उतर गए । हमारे उप नेता के खून की जांच अभी तक नही हो पा रही है ।

डा० कर्ण सिंह : हम करवा देते है खुन की जाच ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : आप दूसरी जाच कर देंगे, खून की जांच तो वहीं पर होगी । मैं जानना चाहता हू आपकी जो एक कमेटी बनी थी उसकी कितनी बैठकें हुई, उसमे कौन कौन सदस्य थे, डाक्टरो के पक्ष के कितने लोग थे और सरकारी पक्ष के कितने लोग थे ? उन्होने जो रिपोर्ट दी है उसमे कौन कौनसा मूल बातें बताई है और उन पर अमल करने मे आपको क्या दिक्कत आ रही है ? इस सबध मे अभी भी चर्चा हुई है तो वह बात भी सामने आ जाये कि आपने जो चर्चा की है डाक्टरो मे उसमे कहा तक मामला सुलझा है ? आप शीघ्र ही इस मामले को निपटाइये, यह बहुत जरूरी है । जो डाक्टर बाहर सर्विस करते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश मे उनको प्रक्टिस न करने का एलाउन्स मिलता है फिर यहा दिल्ली मे क्या दिक्कत है ? आप जल्दी से मामला सुलझाइये वरना उत्तेजना बढ़ेगी और उसके बुरे परिणाम होगे । एक ओर प्रधान मन्त्री अपील करती है कि हडताल समाप्त होनी चाहिए लेकिन जो लोग भूखे मरेंगे वे क्या नही करेंगे ? आप किसी करोडपति को भी चार रोज खाना न दीजिए तो विचलित हो जायेगा । इसलिए मेरा कहना है कि आप जल्दी से इस मामले को समाप्त कीजिए ।

सभापति महोदय : यह ठीक है कि मन्त्री जी के पास 7 मिनट का समय है लेकिन इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि आज भारत का चिकित्सा जगत मन्त्री जी के विचारो को सुनने की प्रतीक्षा कर रहा है, वे यदि चाहें तो कुछ और समय भी ले सकते हैं ।

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (DR. KARAN SINGH): I am very grateful to you for giving me some more time because this is the first time that I shall be speaking in this House after the statement that I laid on the 19th February.

I am sorry my friend. Shri Kachwai, apparently has not read the statement that I made on the 19th or the very comprehensive publication that I placed on the Table of the House. In this publication we not only reproduced the Government's point of view, the letters of the junior doctors received from time to time and the report of the Kartar Singh Committee and their recommendations but also it is a complete and detailed statement..

SHRI JAGANNATHRAO JOSHI: It is all in English.

DR. KARAN SINGH: There is the Hindi version also placed on the Table of the House. It is a long story and I just want to go through one or two things.

Firstly, it is quite clear that the problem of the junior doctors that we are facing to-day is a cumulative problem It is the result of grievances that have accumulated over the last 10- 15 years. It is not a problem that has been immediately created.

The junior doctors feel and, I must say, with a certain degree of justification, that over all these years, they have really had to go through very difficult times and, therefore, this discontent and anger has been simmering and the explosion that we see to-day is the result of this cumulative grievance.

There are two ways in which this problem can be finally solved. One is a long range one and the other is of a short range. Now, as a long range solution, I mentioned on the floor of the House that the Government had decided to set up a Medical Education Commission because the very system of medical education that we have now adopted and that we have inherited very largely from the British, involved a good deal of strain and pressure upon these junior doctors.

This is not a new thing that we have introduced. The British system of Education which has been extant in India for many decades required that these junior doctors go through a very tough time in order to get their post-graduate degrees and their further specialisation. So, this problem cannot, Sir, really be fully solved unless the matter is looked at from a national point of view and the problem is looked upon by a really competent commission and it is for this reason that this Medical Education Commission that we intend to set up is going to go into all these matters very carefully and is going to see what can be done to make Medical Education more responsive to the needs of the nation.

Many people sitting in this House represent rural areas. We have a peculiar situation in which all the doctors are very largely concentrated in the urban areas and in the rural areas you do not get doctors to go there. I am not blaming the doctors. I am simply saying that a reorientation and restructuring is required. These I hope the Medical Education Commission will do. That is a long-range aspect. When I say long-range, I should say, between one to two years.

Then I come to the immediate and the short-term problem. We have reproduced in the note the whole situation leading up to the agreement and the Health Secretary's letter of 31st of March. One point is there which I would like to make clear and it is this. This letter of 31st of March has very carefully been examined from many points of view including the legal point of view and we are advised that what we have done does in fact fulfil all the commitments made in this letter. Now, here is a

[Dr. Karan Singh]

difference of interpretation. The doctors say, you have not fulfilled it; several Members have also said that. But I can say that we have had this studied and it says—if you please see Shri Ramachandran's letter—in paragraph 4, it speaks of suitable running graded pay-scales and allowances and it also speaks of suitable graded scales and emoluments. What we have given them now is an improvement on the Kartar Singh Committee's recommendations. They gave Rs. 450. Rs. 500 and Rs. 550. I improved them which is a unique thing; I don't think that has ever been done in the history of the Government of India before that within 48 hours of the report being received it was improved. I gave them Rs. 500, Rs. 550 and Rs. 600. This is surely a graded scale of emoluments. Then, Sir, they came to me and they said they want this to become sensitive to price rise; after all if the price goes up how are you going to expect us to meet the situation. I have offered them and made this statement on the floor of the other House. I offered to break this up into graded pay-scales with dearness allowance and C.C.A. I have made that offer also.

Now the only problem is with regard to NPA. Unfortunately in this agreement there is no mention as such of NPA.

मुझे फैज का एक शेर याद आ गया है। वह कहते हैं :

वह बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था
वह बात उनको बहुत नागवार गुजरा है।

Why should I, Sir, stand in the way of the agreement? I would be the happiest person to give them more; they are brilliant young people, they are the cream of the intelligensia in this country; they are young men and women and all of them don't come from rich families; they come from middle-class families; some of them come from poor families whose parents have starved and slaved so that these people can have their education. It is not—I can assure you, Sir—that we have been in any way reluctant to fulfil our obligations. After all, the Government of India is spending crores of rupees on other things and if according to some agreement we had to give more, why should I grudge it?

SHRI S. M. BANERJEE: Why should they not be entitled to non-practising allowance?

DR. KARAN SINGH: The point is this. There are two things. One is the agreement. I think this point we have to make clear. In fairness to the Government I must make it clear that our understanding is that what we have now given them does fulfil the agreement made by the Health Secretary. That is our situation. I want to be very clear. Because, after all, agreements are more important really than the money. We do not want to be accused of being a Government which does not fulfil its contracts or agreements

18.00 hrs.

We feel that we have done it. They do not unfortunately argee You may say that this is a difference of interpretation. You may say that it is a legal interpretation. We have had all the things studied fully. That is one point.

But leave the agreement to one side. Let us say there was no agreement, even then it is my duty as Health Minister to see that these young people get better deal. I am not quibbling on am not trying to cheat them or make any sort of argument Forget the agreement. I want to give them more. I would submit that although they may not be satisfied with what we have given for the first time in ten years we have actually offered them more. It may not satisfy them. I am not suggesting that it satisfies.

My only plea is this. When they first met me before the strike, I said to them that I would see that they get good deal as good a deal as was possible in the circumstances. The Kartar Singh Committee contained three doctors and three civil servants; it was not composed of civil servants only but three very eminent doctors were there. This committee after having gone rightly or wrongly recommended a certain set of figure, Rs. 450, Rs. 500 and Rs. 550, I increased that. Some people are now telling me that I should not have increased it, and they are saying 'You made a mistake; you were not a politician; if you had been a politician you would have first of all announced the committee, then there would have been a lot of *shor*,' then you could have called them and said 'Here is another Rs. 50' It may be so, and I plead guilty to that because I made a genuine attempt. I felt that a doctor should be given as much as possible. They started at Rs. 450. I said that we should give them at least Rs. 500 and I announced that.

As hon. Members have said the strike now is rapidly becoming an intolerable situation. The poorer sections of society are suffering. The hospitals are suffering. The rich people can always go to a private practitioner, but the poorer sections of society are hit, and if I may submit, the poorer section of the doctors also people who do not have any background or financial backing are also really the ones that suffer. There are some affluent doctors also who could not care less. But this is beginning to have a very very unfortunate effect upon the hospitals. 63 or 64 days have elapsed, and we have used the greatest restraint to keep things from deteriorating. But the position that has now arisen is this that by their insistence on remaining on strike they are making it very difficult for me to help them in a genuine way. I appeal to them. Many other people have appealed to them. I said 'Look' I have given you something for the first time, something concrete. Please go back to your hospitals; go back to your noble profession, and I as Health Minister will try my best to get you more' Several people have spoken to me. The Delhi Medical Association met me today. Obviously they also represent the doctors; the other members in the profession have also talked to me. Many MPs also have spoken to me about this. I myself am most anxious and most keen that this very unfortunate and unhappy situation must come to an end.

But you will permit me to say that this business of remaining on strike and saying that 'Until you accede to our demands, we do not go back' makes the situation very difficult. I do not want to go into too many details, but this makes it even difficult for me to get them what I want to give them.

For example, take the question of NPA for senior registrars. They came to me and said 'Why should senior residents or registrars not get NPA?. I said, 'Look, if you have a good case for NPA, you may come to me. Go back to your hospitals, and create an atmosphere, and I shall take up your case for NPA with the Cabinet, and I would fight your case for you and I shall be your vakil'. But. By their continuing on strike, I am afraid, the attitude of Government is not going to become more helpful, but it is going to be less helpful.

SHRI S. M. BANERJEE: In this particular case, may I remind the hon. Minister that the insurance employees remained on strike but still a settlement was reached. Let him not try to follow Air Chief Marshal Lal every time. It is not going to work in the country.

DR. KAILAS (Bombay South): May I submit one thing? Let him not advise them to go on strike now; let him also appeal.

DR. KARAN SINGH: May I say one thing? The doctor's profession is

[Dr. Karan Singh]

qualitatively different from the airlines profession or the life insurance profession. The doctor's profession is concerned with human suffering and human life. Therefore, their trying to give up work and to try and use that as a pressure upon Government is not wise, and I can assure you that it is beginning to be counter-productive. I do not know whether Mr. Banerjee plays bridge; I think he does play bridge. You may have a very good hand for three no trumps, but if you bid a slam, a little slam on that, you will lose even the three no trumps.

So my point is that they had a case They had a case. I was with them. The House was with them. The country was with them But I would submit...

MR. CHAIRMAN: Are you prepared to keep that in mind yourself

डा कर्ण सिंह : मुझ से उन्होंने पूछा कि आप का दरवाजा तो बन्द नही है ? भला मैं यह गुस्ताखी कैसे कर सकता हूं कि अपना दरवाजा बन्द रखूं । और मैं तो सौभाग्य से अपने ही मकान में रहता हूं इसलिए मेरा दरवाजा तो बन्द नही रहता है । वह लोग मेरे द्वार के बाहर बैठे हुए है, मुझे उन को देख कर बडा दुख होता है कि यह पढे लिखे नौजवान इन को हंगर स्ट्राइक करनी पडे । झूठी प्रतिष्ठा का प्रश्न नही है । मैं यह कहना चाहता हूं मदन के स्तर पर कि कोई झूठी प्रतिष्ठा का प्रश्न नही है । मेरी प्रतिष्ठा और मेडिकल प्रौफेशन की प्रतिष्ठा बराबर है । जब मैं स्वास्थ्य मत्री बना था तो मेरे दिमाग में इस प्रौफ़ेशन के बारे में बहुत ही उच्च विचार थे और आज भी हैं । मेडिकल प्रौफ़ेशन की प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है ।

It is my duty to look upon it and I look upon the medical profession not as just another profession; I look upon it as a really noble profession. I have come into this Ministry with a certain idealism. But I would again appeal to these people: You are making it more and more difficult for me to help you.

अब मैं समझता नही हू कि इस से ज्यादा और क्या स्पष्ट कहू । स्थिति बिगड़ रही है, दिन प्रति दिन वह। मे मेरे ऊपर प्रैशर है कि अगर नही आते है तो इन को निकाल कर यू०पी०एस०सी० के जरिये डाक्टर ले लीजिये । माननीय मिश्रा जी ने कहा, यू०पी०एस०सी० के जरिये जो डाक्टर आ त है एक तो वह आल इडिया कम्पटीशन होता है, दूसरे शेड्युल्ड कास्टस और शेडयुल्ड ट्राइब्स के लिये रिजर्वेशन होता है, तीसरे आल इडिया उन की ट्रासफ़रेबिलिटी होती है, वह अडमान जा सकता है, लक्षद्वीप जा सकता है, चौथे मिलिट्री सर्विस की लाये-बिलिटी हो सकती है । तो यह सारा सिस्टम खत्म हो जाय और उस के बजाय यू०पी०एस०सी० के माध्यम से ले ले तो यह इन्ही के हित मे नही होगा ।

That is not going to be in the interest of these people ultimately.

I would appeal to all members of the House that they should advise these young people that they should not press this thing to a confrontation at this time. It will not be in their interest. They should have some faith in me We have already shown our faith. I will look into their grievances. Hon. members of the House are interested. Several MPs, many from my party and others, came to me and said that 'we are genuinely concerned'. But these people must not remain on strike If they remain on strike, they are, in a way, trying to use the misery of the patients in order to bring pressure on Government, and I am afraid that government pressure, government attitude, is going to be more difficult.

मुझे प्रसन्नता है कि एक कार्टून में मुझे उन्होंने पहले कुम्भकरण बनाया था। वह भी गलत था क्योंकि मैं सोता तो अच्छा हूं और मेरी कांशेंस भी क्लीयर है । लेकिन अब मुझे उन्होंने दानी कर्ण बना दिया । अगर मैं दानी कर्ण होता तो मैं तो सवा मन सोना इन को दे देता । मैंने कहा कि मैं ने तो प्रिवी पर्स भी छोड़ दिया, अगर वही होता तो 10 लाख रु० दे देता और फ़ैसला हो जाता । लेकिन आज तो वह भी स्थिति नहीं रही है । तो एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है । प्रश्न सरकार का है, हुकूमत का है ।

I would appeal very sincerely on the floor of the House to the junior doctors. Some of them may be here. Some of them may read what I have said. I would again appeal to them with all the earnestness at my command: please do not take this thing to a confrontation which will ultimately help neither the people nor the public. We have given you a fair deal, what we consider a fair deal. Go back to your work. I will take up your issue whatever issues.

They do not probably have rooms to stay. I will give priority in the Fifth plan to hostels. Whatever money I have got, I will give priority to buildings. But they must give me an opportunity. They must not oppose this. I would urge that this is the sense of the House.

DR. KAILASH: When they come back, you will not punish them.

Dr. Karan Singh: This is also

~~DR. KAILAS: When they come~~ becoming more and more difficult.—if they come back as quickly as possible. The situation is already getting more and more difficult. There have certain terminations. Other problems are there. It will become more and more difficult to unscramble them. I am perhaps in a way standing between them and a total break. They must have faith in me. I can assure you this is not a party matter. This is not a question for any particular party. This is a question all of us want to slove, all men of goodwill want to settle. As you try rightly said, this is beginning to affect not only Delhi; the whole medical profession in India is beginning to be adversely affected.

Therefore, I will conclude, though it is a very long story, I appreciate and fully share the sense of urgency and distress felt by all hon. members on both sides of the House. My appeal again would be, on my own, and if I may submit, on behalf of all of you here: please ask these people to go back to work to have some faith in me. I will do whatever is best to help them in solving the remainder of their problems. This is all I can say on the floor of the House.

18.10 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

PROCLAMATION IN RELATION TO THE STATE OF MANIPUR UNDER ARTICLE 356 OF THE CONSTITUTION.

MR. CHAIRMAN: The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): Sir I beg to place on the Table a copy of the Proclamation issued by the President of India under clause (2) of article 356 of the Constitution of India revoking the Proclamation made under the said rule on the 28th March, 1973, in relation to the State of Manipur. [*Placed in library. See* No. LT-6309/74].

18.11 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, March 5, 1974/Phalguna 14, 1895 (*Saka*).

MGIPND—M—3731 L S—978